Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to address water-shortage problem in Bundelkhand region.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखण्ड में कई जिलों में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। इस वर्ष भी बुंदेलखण्ड में सूखे के हालात बन सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार बुंदेलखण्ड में पिछले कई दशकों से औसत वर्षा 50-60 सेंटीमीटर ही रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत वर्षा 117 सेंटीमीटर से बहुत कम है। इस वर्ष भी मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत महोबा में 40 फीसदी कम बारिश हुई। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर सहित पूरे बुंदेलखण्ड में सूखे के कारण कृषि पर बुरा असर पड़ सकता है और यह हालात इस स्थिति में बन रहे हैं जब विगत कई दशकों से बुंदेलखण्ड में लगातार सूखा पड़ रहा है। महोबा में जहाँ कोई नदी नहीं है, यह इलाका पूरी तरह से वर्षा जल और उसके संचयन पर निर्भर है।

बुंदेलखण्ड क्षेत्र काफी शुष्क क्षेत्र होने के कारण सरकार की प्राथमिकता पर है और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए सरकार द्वारा न सिर्फ जल प्रबंधन अपितु किसानों की ऋण माफी जैसे वित्तीय उपाय सहित अनेक राहत के उपाय किए गए हैं। परंतु पेयजल और सिंचाई हेतु जल संचयन के साथ-साथ जल की उपलब्धता भी अत्यंत आवश्यक है।

यद्यपि बुंदेलखण्ड में लगभग 7000 तालाब, कीरत सागर, मदन सागर जैसे बड़े तालाब एवं सलारपुर व मझगवां इत्यादि जैसे बांध है और केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। परंतु इस विशाल जल संचयन संरचना की उपस्थिति के उपरांत भी पेयजल और सिंचाई जल प्रबंधन एक गंभीर समस्या है। इसका मुख्य कारण इन जल संग्रहण संरचनाओं के उचित रख-रखाव का अभाव और विगत कुछ दशकों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार कम हो रही वर्षा है।

इस क्रम में देश की विभिन्न जटिल सामाजिक समस्याओं का हल निकालने हेतु इप्रिंट योजना मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत आई.आई.टी. कानपुर द्वारा बुंदेलखण्ड में सूखे की समस्या से निजात दिलाने हेतु स्वदेशी और काफी सस्ती कृत्रिम वर्षा तकनीक विकसित की गई है, जिसके उपयोग से पूरा बुंदेलखण्ड काफी लाभान्वित होगा।

अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि बुंदेलखण्ड में सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के साथ-साथ तालाबों, बांधों से सिल्ट निकालकर उनका उचित रख-रखाव करके किसानों को राहत प्रदान की जाए।